नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 251
दि. 14.06.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आसमान के वीरों का अंतिम मिशन: AN-32 हादसे ने फिर उठाए सैन्य विमान सुरक्षा पर सवाल

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा के लिए हर दिन आसमान में उड़ान भरने वाले वायुसेना के जांबाज जवानों का जीवन साहस, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक होता है। लेकिन कभी-कभी वही आसमान, जो उनकी कर्मभूमि होता है, उनके जीवन का अंतिम पड़ाव भी बन जाता है। शनिवार सुबह असम के जोरहाट स्थित वायुसेना एयरबेस पर हुआ एएन-32 विमान हादसा देश को गहरे शोक में डुबो गया। नियमित उड़ान के दौरान लैंडिंग प्रक्रिया के समय वायुसेना का परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो अधिकारियों और दो अग्निवीरों सहित पांच वायुसेना कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। एक अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका उपचार जारी है।

यह दुर्घटना केवल एक विमान हादसा नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति है जिन्होंने अपने बेटे, पति, भाई और साथी को देश सेवा के लिए समर्पित किया था। शहीद होने वालों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर (वायु) खेमाराम कुमावत और अग्निवीर (वायु) दानिश आलम शामिल हैं। इन सभी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायुसेना का एएन-32 विमान शनिवार सुबह लगभग 10 बजे नियमित प्रशिक्षण और परिचालन गतिविधि के तहत उड़ान भर रहा था। विमान जब जोरहाट एयरबेस पर उतरने की प्रक्रिया में था, उसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि विमान को भारी क्षति पहुंची और उसमें सवार पांच वायुसेना कर्मियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल सक्रिय हो गए और विमान में फंसे कर्मियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया।

बचाव दल ने विमान के को-पायलट को गंभीर रूप से घायल अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

हादसे की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान जारी

कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वायुसेना ने कहा कि इन वीर सैनिकों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है और राष्ट्र उनके योगदान को सदैव याद रखेगा।

वायुसेना ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि पूरा वायुसेना परिवार इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। सैन्य बलों में किसी भी जवान का निधन केवल एक व्यक्ति की क्षति नहीं होता, बल्कि पूरे सैन्य परिवार और राष्ट्र के लिए भावनात्मक आघात होता है। यही कारण है कि इस दुर्घटना ने वायुसेना के प्रत्येक सदस्य को गहराई से प्रभावित किया है।

दुर्घटना के कारणों का अभी तक आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। वायुसेना ने घटना की विस्तृत जांच के लिए 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' के आदेश दे दिए हैं। जांच दल विमान के तकनीकी रिकॉर्ड, उड़ान संबंधी आंकड़ों, मौसम की स्थिति, संचार रिकॉर्ड तथा अन्य सभी संभावित कारणों का अध्ययन करेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इस दुर्घटना ने एक बार फिर एएन-32 विमान के सुरक्षा रिकॉर्ड को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एएन-32 सोवियत संघ में विकसित एक मध्यम श्रेणी का सैन्य परिवहन विमान है, जिसे विशेष रूप से कठिन मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। भारतीय वायुसेना ने इसे 1980 के दशक में अपने परिवहन बेड़े का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। यह विमान वर्षों से सैनिकों, हथियारों, राहत सामग्री और आवश्यक सैन्य उपकरणों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। एएन-32 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कठिन परिस्थितियों में उड़ान भरने की क्षमता रही है। हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में इस विमान ने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को मजबूत किया है। कारगिल युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत अभियानों तक, इस विमान ने कई महत्वपूर्ण मिशनों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।

हालांकि, इसकी उपयोगिता के बावजूद इसका सुरक्षा रिकॉर्ड चिंता का विषय रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 से अब तक एएन-32 विमानों से जुड़ी 18 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें कई दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों की जान गई है। समय-समय पर इन विमानों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

वर्ष 2009 में एक बड़ी दुर्घटना के बाद भारत ने यूक्रेन के साथ लगभग 400 मिलियन डॉलर का समझौता किया था। इस कार्यक्रम के तहत 55 से अधिक एएन-32 विमानों का आधुनिकीकरण किया गया। इनमें नए एवियोनिक्स, आधुनिक नेविगेशन प्रणाली, उन्नत संचार उपकरण और आपातकालीन लोकेटर सिस्टम लगाए गए थे। उद्देश्य था विमानों की परिचालन क्षमता और सुरक्षा स्तर को बेहतर बनाना। इसके बावजूद समय-समय पर होने वाली दुर्घटनाएं यह संकेत देती हैं कि विमान बेड़े के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को और तेज करने की आवश्यकता हो सकती है।

सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी विमान की सुरक्षा केवल उसके तकनीकी ढांचे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि रखरखाव, प्रशिक्षण, मौसम, परिचालन परिस्थितियों और अनेक अन्य कारकों का भी इसमें योगदान होता है। इसलिए इस दुर्घटना की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिर भी यह हादसा निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े की भविष्य की रणनीति पर चर्चा को और तेज करेगा।

राष्ट्र की रक्षा में जुटे सैनिकों का जीवन सदैव जोखिमों से भरा होता है। सीमाओं पर तैनाती हो या आसमान में उड़ान, वे हर क्षण देश की सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। जोरहाट में शहीद हुए पांचों वायुसेना कर्मियों ने भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

आज पूरा देश इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है। उनकी शहादत केवल एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। जब भी भारतीय वायुसेना के साहसिक अभियानों और बलिदानों का इतिहास लिखा जाएगा, तब जोरहाट के इस हादसे में शहीद हुए इन वीरों का नाम सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाएगा। उनकी कुर्बानी देशवासियों को यह याद दिलाती रहेगी कि हमारी सुरक्षा के पीछे अनगिनत सैनिकों का त्याग और समर्पण छिपा हुआ है, जिनके कारण राष्ट्र निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है।

सियासत में बदले सुर: टकराव से मेल-मिलाप तक पहुंची कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कहानी

कोलकाता। राजनीति में रिश्ते और बयान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी तीखी आलोचना, कभी सार्वजनिक नाराजगी और कभी अचानक नरम पड़ते तेवर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा ही एक घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कुछ समय पहले जिस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखा था, अब उन्हीं के प्रति अपने रवैये में उल्लेखनीय नरमी दिखाते हुए उन्हें बेटे के समान बताया है। उनके इस बदले हुए रुख ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

हाल के दिनों में कल्याण बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेदों की खबरें लगातार सुर्खियों में थीं। मामला इतना आगे बढ़ गया था कि कल्याण बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने यह तक कह दिया था कि उन्हें अभिषेक बनर्जी और उनके बीच किसी एक को चुनना होगा। यह बयान राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि इसे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के संकेत के रूप में देखा गया।

उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों नेताओं के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि उसे पाटना आसान नहीं होगा। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और अब वही कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी के प्रति स्नेह और अपनापन जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक उनके बेटे जैसे हैं और एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बेटे की गलतियों को माफ कर दे। उनके इस बयान को राजनीतिक पर्यवेक्षक केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं।

कल्याण बनर्जी ने अपने ताजा बयान में केवल व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं की बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और राज्य में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई, जहां विपक्ष लगभग पूरी तरह समाप्त होता दिखाई दे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। उनके इन बयानों ने यह संकेत दिया कि व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद वह व्यापक राजनीतिक मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाना चाहते हैं।

दरअसल दोनों नेताओं के बीच तनाव की शुरुआत उस समय हुई थी जब फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी ने अदालत में अपनी पैरवी के लिए कल्याण बनर्जी की जगह किसी अन्य वरिष्ठ वकील को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। बताया गया कि इस मामले में वकील किशोर दत्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि कल्याण बनर्जी को इससे अलग रखा गया। यह फैसला कल्याण बनर्जी को बेहद नागवार गुजरा था और उन्होंने इसे अपने प्रति अनादर और अविश्वास के रूप में देखा।

उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि उन्हें उनके बेटे के माध्यम से जानकारी दी गई कि अब उन्हें अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि अभिषेक बनर्जी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना नहीं जानते और उन पर कभी भरोसा नहीं करते थे। उनके ये बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बने थे और माना जा रहा था कि इससे पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।

कल्याण बनर्जी की नाराजगी सामने आने के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी अपेक्षाकृत संयमित प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि कल्याण बनर्जी उनसे बड़े हैं और उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें बचपन से देखा है और वह उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बनर्जी के इस संतुलित और शांत रवैये ने तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अब जब कल्याण बनर्जी ने भी अपने तेवर नरम कर लिए हैं तो इसे दोनों नेताओं के बीच संबंधों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि पार्टी के भीतर मतभेद पूरी तरह समाप्त हो गए हैं या नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर अभी भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन सार्वजनिक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच टकराव की तीव्रता कम होती दिखाई दे रही है।

श्रेय की सियासत और पोस्टर का विवाद: तमिलनाडु में निति आयोग बैठक के बाद बढ़ी राजनीतिक तल्खी

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर श्रेय लेने की राजनीति को लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया है। निति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किए जाने के बाद विपक्ष ने उन पर राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मंच का उपयोग अपनी सरकार के प्रचार और राजनीतिक छवि निर्माण के लिए किया, जबकि जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया गया, उनमें से अधिकांश पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों और वर्षों की मेहनत का परिणाम हैं। इस मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति में नया सियासी संग्राम छेड़ दिया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

निति आयोग की बैठक सामान्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विकास, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच मानी जाती है। लेकिन इस बार तमिलनाडु की ओर से प्रस्तुत उपलब्धियों को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की उपलब्धियों को अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जबकि उनकी सरकार को सत्ता संभाले अभी बहुत कम समय हुआ है। दूसरी ओर सत्तापक्ष का मानना है कि मुख्यमंत्री ने राज्य की समग्र प्रगति का उल्लेख किया और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री विजय ने बैठक के दौरान तमिलनाडु को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, महिलाओं की कार्यबल में उल्लेखनीय भागीदारी, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सुरक्षा और स्वयं सहायता समूहों की सफलता जैसे कई बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये उपलब्धियां वर्तमान सरकार के एक महीने के कार्यकाल की देन हैं या फिर वे उन नीतियों और कार्यक्रमों का परिणाम हैं जिन पर वर्षों तक काम किया गया। उनके अनुसार जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसी भी उपलब्धि का वास्तविक श्रेय किसे जाता है।

विपक्ष का कहना है कि किसी भी राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति अचानक नहीं होती। इसके पीछे वर्षों की नीतिगत निरंतरता, प्रशासनिक प्रयास और विभिन्न सरकारों के फैसलों का योगदान होता है। ऐसे में यदि कोई नई सरकार उन उपलब्धियों को अपने खाते में दर्ज कराने की कोशिश करती है तो यह राजनीतिक रूप से भ्रामक संदेश देने जैसा है। उदयनिधि ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने निति आयोग जैसे महत्वपूर्ण मंच का उपयोग राज्य की वास्तविक स्थिति बताने के बजाय राजनीतिक प्रचार के लिए किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल उपलब्धियों के श्रेय तक सीमित नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से ही राजनीतिक दल अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में विकास कार्यों और उपलब्धियों को लेकर होने वाली बहसें स्वाभाविक रूप से अधिक तीखी हो जाती हैं। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राज्य की प्रगति में उसका योगदान अधिक रहा है, जबकि सरकार वर्तमान नेतृत्व की भूमिका को प्रमुखता देना चाहती है।

विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर मुख्यमंत्री विजय के रुख से जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का वर्तमान रुख उनके चुनावी बयानों से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने नीट के मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, जबकि निति आयोग की बैठक में उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा के अंकों को अधिक महत्व देने की बात कही। विपक्ष का दावा है कि दोनों रुखों में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है।

तमिलनाडु में नीट लंबे समय से एक संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। राज्य के कई राजनीतिक दलों का तर्क रहा है कि यह परीक्षा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। वहीं दूसरी ओर इसके समर्थकों का कहना है कि देशभर में मेडिकल शिक्षा में एक समान मानक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। इसी कारण जब भी कोई राजनीतिक नेता नीट पर बयान देता है तो वह व्यापक चर्चा और बहस का विषय बन जाता है।

उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि जनता को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सरकार की वास्तविक नीति क्या है। यदि सरकार बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश का समर्थन करती है तो उसे इस विषय पर स्पष्ट नीति दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। उनका आरोप है कि विभिन्न मंचों पर अलग-अलग बातें कहने से छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सत्तारूढ़ पक्ष के समर्थकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री विजय ने निति आयोग की बैठक में तमिलनाडु के हितों को मजबूती से रखा और राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। उनके अनुसार किसी भी मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वह अपने राज्य की प्रगति और आवश्यकताओं को देश के सामने रखे। वे यह भी कहते हैं कि राज्य की उपलब्धियां किसी एक सरकार या एक नेता की नहीं होतीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे और समाज के सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती हैं।

हालांकि विपक्ष इस तर्क से संतुष्ट नहीं दिख रहा। उसका मानना है कि उपलब्धियों का उल्लेख करते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वे किन नीतियों और किस अवधि के दौरान हासिल हुईं। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय भविष्य की चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

तमिलनाडु की राजनीति में पोस्टर, प्रचार और राजनीतिक संदेशों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। राज्य के राजनीतिक इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के श्रेय को लेकर बड़े विवाद खड़े हुए हैं।

आस्था की पारदर्शिता की परीक्षा: राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच अब एसआईटी के हवाले

अयोध्या। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे को लेकर सामने आए कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों ने देशभर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान राशि से जुड़ी खबरों के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित यह जांच दल अब पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल करेगा और निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस कदम को मंदिर प्रशासन और सरकार द्वारा पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर गठित इस विशेष जांच दल को मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच का दायित्व सौंपा गया है। सरकार ने एसआईटी को सात दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट तथा 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच की समयबद्ध प्रक्रिया यह संकेत देती है कि शासन इस मामले को शीघ्रता और गंभीरता के साथ निपटाना चाहता है ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या भ्रम की स्थिति को समाप्त किया जा सके।

गठित एसआईटी में प्रशासनिक, पुलिस और वित्तीय मामलों के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच समिति की अध्यक्षता लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत करेंगे। उनके साथ रेंज की आईजी किरन एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को भी सदस्य बनाया गया है। इन अधिकारियों को मंदिर में प्राप्त होने वाले चढ़ावे, दान राशि के प्रबंधन, वित्तीय

अभिलेखों, सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब मंदिर परिसर में तैनात कुछ कर्मचारियों पर दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए। बताया गया कि मंदिर की दान पेटियों से निकाली गई राशि के मिलान के दौरान कुछ रकम कम पाई गई थी। प्रारंभिक स्तर पर सामने आई इन जानकारियों के बाद मंदिर प्रशासन ने आंतरिक जांच शुरू की। इस दौरान कुछ कर्मचारियों से पूछताछ किए जाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की खबरें भी सामने आईं। हालांकि अब तक किसी भी स्तर पर अंतिम रूप से कोई निष्कर्ष घोषित नहीं किया गया है।

राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और आस्था का प्रतीक है। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु मंदिर में श्रद्धा और विश्वास के साथ दान अर्पित करते हैं। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी किसी भी प्रकार की अनियमितता की खबर स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता का कारण बनती है। यही वजह है कि मामला सामने आने के बाद संत समाज, विभिन्न धार्मिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग उठाई।

संतों और धर्माचार्यों का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहां प्राप्त होने वाला प्रत्येक दान भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसलिए चढ़ावे से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उनका मानना है कि निष्पक्ष जांच से न केवल सच्चाई सामने आएगी बल्कि मंदिर प्रशासन की विश्वसनीयता और श्रद्धालुओं का विश्वास भी और मजबूत होगा। राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले ने चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर कोई अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

उनका मानना है कि धार्मिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के बड़े धार्मिक स्थलों पर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में दान राशि प्राप्त होती है। ऐसे में उसके प्रबंधन के लिए अत्यंत मजबूत निगरानी व्यवस्था, डिजिटल रिकॉर्डिंग, बहुस्तरीय सत्यापन और नियमित ऑडिट प्रणाली की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से दान संग्रह और उसके प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। राम मंदिर जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल में भी वित्तीय प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा और निगरानी आवश्यक मानी जाती है। एसआईटी की जांच के दौरान मंदिर की दान पेटियों से प्राप्त राशि का रिकॉर्ड, नकदी गिनती की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की भूमिका, सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। जांच दल यह भी देखेगा कि कहीं प्रक्रियागत कमियां या निगरानी व्यवस्था में कोई खामी तो नहीं थी, जिसके कारण इस प्रकार के आरोप सामने आए। यदि किसी व्यक्ति या समूह की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा यह दर्शाती है कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाएगा। सात दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के निर्देशों से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे श्रद्धालुओं के बीच फैली आशंकाओं का भी समाधान होगा। राम मंदिर देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में उससे जुड़े किसी भी विवाद का प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। यही कारण है कि इस मामले की जांच पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं। फिलहाल जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संबंधित अधिकारी विभिन्न दस्तावेजों तथा तथ्यों का परीक्षण कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। तब तक प्रशासन और वायु में फैली अटकलों से दूर रहकर आधिकारिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की अपील की जा रही है। आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाएगी और यह तय करेगी कि आरोपों के पीछे वास्तविक तथ्य क्या हैं।

संपादकीय

अक्षम्य है भारतीय नाविकों का मारा जाना

खाड़ी में ईरान की नाकेबंदी की कवायद के दौरान अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों का मारा जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको लेकर देश में गम व गुस्सा व्याप्त है। यूं तो कहा जाता रहा है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और क्वॉड जैसे संगठनों में भूमिका निभा रहा है, तो फिर लगातार भारत के हितों पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? भले ही अमेरिका ईरान की तेल निर्यात से होने वाली आय रोकने व युद्ध समाप्त करने हेतु समझौते के लिये दबाव बनाने हेतु ये आक्रामक नीति अपना रहा हो। लेकिन जिन देशों का युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, उनके नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हाल में भारतीय चालक दल वाले तीन टैंकरों को अमेरिकी सेना द्वारा निशाना बनाया गया है। इसमें से, ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय चालक दल के तीन सदस्य मारे गये हैं। जिससे भारत व अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वैसे औपचारिक विरोध दर्ज करते हुए भारत ने दिल्ली में एक अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया है। इसके बावजूद भारत के खिलाफ लगातार नकारात्मक रवैया दर्शाने वाले अमेरिका के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद कि भारत क्वॉड में अमेरिका का साझेदार है। विडंबना यह भी है कि जो सूत्रधार संगठन के जरिये समुद्री आवाजाही को स्वतंत्र बनाने की बात करता है, वही अमेरिका इसमें बाधक बना है। भले ही अमेरिका इन जहाजों के प्रतिबंधित होने की बात कहे, या जहाज भारतीय न हों, लेकिन उनमें चालक दल के सदस्य तो भारतीय थे। इसकी जानकारी स्वाभाविक रूप से अमेरिका के खुफिया तंत्र को जरूर रही होगी। अमेरिका को सार्वजनिक रूप से भारतीय नाविकों के मारे जाने पर खेद जताना चाहिए। निश्चय ही भारत के निकट के समुद्री क्षेत्र में अमेरिका का निरंकुश व्यवहार निंदनीय है। कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इस मुद्दे को सख्ती से अमेरिका के सामने उठाना चाहिए था।

तमाम भारतीयों को इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया उदार लगती है। सवाल पूछा जा रहा है कि यदि तीन अमेरिकी नागरिक मारे जाते तो क्या अमेरिका चुप बैठता? कहा जा रहा है कि भारत का कड़ा विरोध सामने न आने के कारण होर्मुज स्ट्रेट के पास पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय के मारे जाने की घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम चर्चा हुई है। विडंबना है कि अमेरिकी सेना ने एक सप्ताह में भारतीय चालक दल वाले तीन टैंकरों को निशाना बनाया। हालांकि, सोमवार को हुए हवाई हमले के बाद ओमानी अधिकारियों ने 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया था। दरअसल, ट्रंप प्रशासन की निरंकुशता के चलते ही अमेरिका रवैया वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कारोबारी जहाजों को निशाना बनाने का क्या औचित्य है? अमेरिका को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह तटस्थ देशों के नागरिकों को निशाना बनाये? क्यों भारतीय नागरिक अमेरिका व ईरान के बीच जारी संघर्ष की कीमत चुकाएं? इस तरह का शक्ति प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है तथा स्वतंत्र नौवहन के मार्ग में बाधक है। भारतीयों का गुस्सा तब कम हो जाता यदि अमेरिका मरने वाले नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर देता। सही मायने में अमेरिका भारत को अपने कारोबारी हितों के साधन के रूप में तो इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारतीय आत्मसम्मान व संप्रभुता का मान नहीं रखता। भारत को बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ही अपनी कूटनीति का निर्धारण करना चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि भारत एक उभरता बाजार ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। अब चाहे सामने अमेरिका हो या चीन जैसे कोई अन्य देश। भले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कई जहाज भारत के स्वामित्व वाले न हों, लेकिन चालक दलों में शामिल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए।

गृहिणी राष्ट्रनिर्माता है तो हिंसा की शिकार क्यों?

“ आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला सशक्तीकरण को बहुआयामी दृष्टि से देखा जाए। महिलाओं के घरेलू श्रम को मान्यता देने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। विद्यालयों और परिवारों में लैंगिक समानता के संस्कार विकसित किए जाएं। पुरुषों और लड़कों को भी इस परिवर्तन प्रक्रिया का भाग बनाया जाए।

भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। उन्हें 'आधी आबादी' और विकास की समान भागीदार कहा जाता है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई जाती है। सरकारें महिला सशक्तीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती हैं और समाज भी महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करता है। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जो हमें इस सशक्तीकरण के वास्तविक स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें 'नेशन बिल्डर' अर्थात् राष्ट्रनिर्माता कहा। न्यायालय ने यह भी माना कि घरेलू कार्यों और परिवार की देखभाल में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले श्रम का आर्थिक मूल्य है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक चौथी तथा शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती है। यह स्थिति एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। जिस महिला को राष्ट्रनिर्माता कहा जा रहा है, वही महिला अपने घर, परिवार और समाज में असुरक्षा और हिंसा का सामना करने को विवश है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय समाज में महिलाओं के अवैतनिक श्रम को मान्यता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सदियों से गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को केवल कर्तव्य या प्रेम का विस्तार मान लिया गया। घर की सफाई, भोजन बनाना, बच्चों का पालन-पोषण, बुजुर्गों की सेवा, परिवार के स्वास्थ्य और संस्कारों की रक्षा, घरेलू प्रबंधन और सामाजिक संबंधों का निर्वहन-इन सभी कार्यों को महिलाओं का स्वाभाविक दायित्व माना गया। परिणामस्वरूप उनके श्रम को कभी आर्थिक दृष्टि से नहीं आंका गया। वास्तव में यदि किसी परिवार में गृहिणी द्वारा किए जाने वाले सभी

कार्यों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, तो उस पर भारी आर्थिक व्यय आएगा। इसके बावजूद गृहिणी के श्रम को न तो वेतन मिलता है और न ही सामाजिक मान्यता। वह चौबीस घंटे और वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिन कार्यरत रहती है। उसका कोई अवकाश नहीं होता, कोई पदोन्नति नहीं होती और कोई सेवानिवृत्ति नहीं होती। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना कि गृहिणी केवल परिवार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देती है, सामाजिक चेतना को नई दिशा देने वाला विचार है।

न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में गृहिणी की सेवाओं का मूल्यांकन न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह के आधार पर करने की बात कही। यह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता को चुनौती है जो घरेलू श्रम को महत्वहीन समझती रही है। वास्तव में महिलाओं का यह अदृश्य श्रम देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। यदि इस श्रम का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और उसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शामिल किया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर काफी बदल सकती है। लेकिन इसी संदर्भ में दूसरा पक्ष और भी अधिक चिंता पैदा करता है। जिस महिला के योगदान को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र निर्माण का आधार मान रहा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने सफल 12 वर्ष के रिकार्ड प्रधानमंत्री शासन की आयोजनाओं के अवसर पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सम्मान की अधिकारी मान कर रहे हैं, क्या उसे वह सम्मान, सुरक्षा और गरिमा प्राप्त है जिसकी वह अधिकारी है? दुर्भाग्य से इसका उत्तर संतोषजनक नहीं है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आज भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चौथी महिला और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक छठी महिला हिंसा का सामना करती है। 18 से 49 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में लगभग 22 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि उन्हें वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा झेलनी पड़ी। यह स्थिति एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। जिस महिला को राष्ट्रनिर्माता कहा जा रहा है, वही महिला अपने घर, परिवार और समाज में असुरक्षा और हिंसा का सामना करने को विवश है। यह स्थिति तब है जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए जा चुके हैं और महिला अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि कानून मौजूद हैं, योजनाएं चल रही हैं और महिला सशक्तीकरण को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जा चुका है, तो फिर महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्यों नहीं रुक रही? आखिर क्यों घर से लेकर कार्यस्थल तक महिलाएं स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित महसूस नहीं कर पातीं?

इसका उत्तर केवल कानूनी व्यवस्था में नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में छिपा है। भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित है। महिलाओं को परिवार की धुरी तो माना जाता है, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता और समान अधिकार देने में संकोच किया जाता है। एक ओर उनके श्रम पर परिवार की पूरी व्यवस्था निर्भर रहती है, दूसरी ओर उनके योगदान को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। यही मानसिकता कई बार घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव का कारण बनती है। आज भी दहेज प्रथा समाज पर कलंक बनी हुई है। अनेक शिक्षित परिवारों में भी दहेज की मांग और उससे जुड़े अपराध सामने आते हैं। हाल के वर्षों में दहेज हत्या और उत्पीड़न के अनेक मामले राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने हैं। यह विडंबना ही है कि एक लड़की की शिक्षा, पालन-पोषण और विवाह पर भारी व्यय करने वाले माता-पिता को विवाह के समय अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान पर सीधा आघात है।

इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने, यौन हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वासों तथा सामाजिक पिछड़ेपन के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं अधिक दिखाई देती हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक चेतना का विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। महिला सशक्तीकरण को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व या आर्थिक अवसरों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ है-सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर और स्वतंत्र निर्णय क्षमता। यदि कोई महिला आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन घर में हिंसा का शिकार है, तो उसे पूर्णतः सशक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाए, लेकिन सामाजिक सम्मान न मिले, तो भी सशक्तीकरण अधूरा रहेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला सशक्तीकरण को बहुआयामी दृष्टि से देखा जाए। महिलाओं के घरेलू श्रम को मान्यता देने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। विद्यालयों और परिवारों में लैंगिक समानता के संस्कार विकसित किए जाएं। पुरुषों और लड़कों को भी इस परिवर्तन प्रक्रिया का भाग बनाया जाए। केवल महिलाओं को जागरूक करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समाज की सोच में परिवर्तन लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पुलिस और प्रशासन को महिलाओं से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना होगा। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा ताकि अपराधियों में दंड का भय उत्पन्न हो और पीड़ित महिलाओं को न्याय प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि महिलाओं के अवैतनिक श्रम को राष्ट्रीय आर्थिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाए। समय आ गया है कि घरेलू कार्यों को केवल निजी दायित्व न मानकर सामाजिक और आर्थिक योगदान के रूप में स्वीकार किया जाए। इससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना भी सुदृढ़ होगी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण केवल संसद, उद्योग, सेना या प्रशासन तक सीमित नहीं है। परिवार का निर्माण और उसका संरक्षण भी राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और इस कार्य की सबसे बड़ी वाहक महिला है। लेकिन यदि वही महिला हिंसा, भेदभाव और असुरक्षा का सामना करती रहे, तो राष्ट्र निर्माण का यह सपना अधूरा ही रहेगा। इसलिए आज आवश्यकता केवल महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन करने की नहीं, बल्कि उनके जीवन का मूल्य समझने की है।

प्रेरणा

लोकतंत्र की असली पहचान: जब सबसे कमजोर नागरिक बनता है व्यवस्था का केंद्र

लोकतंत्र केवल चुनावों, संसदों और सरकारों का नाम नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ उस व्यवस्था में छिपा होता है, जहां समाज के सबसे कमजोर, सबसे साधारण और सबसे कम प्रभावशाली व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके शासक कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां का सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस करता है। भारतीय अर्थशास्त्री और गांधीवादी चिंतक जे.सी. कुमारप्पा के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग इसी सत्य को अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है।

एक बार कुमारप्पा भारत सरकार की एक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे। वे किसी विशेष सरकारी वाहन में नहीं, बल्कि एक साधारण घोड़ा-गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया क्योंकि उस मार्ग से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का काफिला गुजरने वाला था। यह उस समय की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया थी, लेकिन कुमारप्पा ने इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि यदि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और एक साधारण गाड़ीवान दोनों समान नागरिक हैं, तो सड़क से हटाया किसे जाना चाहिए—उस व्यक्ति को जो कमजोर है या उस व्यक्ति को जिसके पास सत्ता और संसाधनों की शक्ति है?

पहली नजर में यह प्रश्न केवल एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी लग सकता है, लेकिन इसके भीतर लोकतंत्र का गहरा दर्शन छिपा हुआ था। जब अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह सब सुरक्षा कारणों से किया गया है, तब भी उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि यदि कोई वाहन दूसरे के लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो प्रतिबंध उस पर लगना चाहिए जो अधिक शक्तिशाली है, न कि उस पर जो कमजोर और असुरक्षित है। उनके इस कथन में केवल तर्क नहीं था, बल्कि एक ऐसी दृष्टि थी जो समाज और शासन को सबसे कमजोर व्यक्ति की नजर से देखने की प्रेरणा देती है।

कुमारप्पा का यह विचार उनके संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक दर्शन का आधार था। वे मानते थे कि किसी भी नीति, कानून या योजना का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को कितना लाभ मिलेगा। यदि कोई नीति केवल शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करती है और कमजोर लोगों को और अधिक हाशिए पर धकेल देती है, तो वह लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि अल्पसंख्यक, गरीब, श्रमिक, किसान और वंचित वर्ग भी समान सम्मान और अवसर प्राप्त करें।

आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब कुमारप्पा की यह सोच पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देती है। आधुनिक समाज में विकास, तकनीक और आर्थिक प्रगति को सफलता का प्रतीक माना जाता है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार वाहन और बड़े उद्योग विकास के संकेत समझे जाते हैं। लेकिन यदि इस विकास के बीच गरीब, कमजोर और सामान्य नागरिक की आवाज दब जाए, तो यह विकास अधूरा रह जाता है। लोकतंत्र की असली परीक्षा वहीं होती है जहां सरकार और समाज यह तय करते हैं कि उनकी प्राथमिकता कौन है—शक्ति और प्रभाव रखने वाले लोग या वे लोग जो अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की स्थिति में नहीं हैं।

महात्मा गांधी ने भी इसी विचार को अपने प्रसिद्ध 'अंत्योदय' सिद्धांत में व्यक्त किया था। उनका मानना था कि कोई भी निर्णय लेते समय हमें उस सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करना चाहिए, जिसे उस निर्णय से प्रभावित होना है। यदि हमारा निर्णय उसके जीवन को बेहतर बनाता है, तभी वह सही निर्णय माना जा सकता है। कुमारप्पा गांधी के निकट सहयोगी थे और उन्होंने इसी विचार को अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उनके लिए अर्थव्यवस्था केवल उत्पादन और लाभ का विषय नहीं थी, बल्कि मानव कल्याण का माध्यम थी।

लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत केवल संविधान की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ तब सामने आता है जब सार्वजनिक स्थानों, सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हर व्यक्ति को समान महत्व दिया जाए। यदि किसी सड़क पर एक सामान्य नागरिक को केवल इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि कोई शक्तिशाली व्यक्ति वहां से गुजरने वाला है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में सभी नागरिक समान हैं। यद्यपि सुरक्षा व्यवस्था की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन लोकतंत्र का आदर्श हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि शक्ति का उपयोग सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए होना चाहिए।

कुमारप्पा का दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाता है कि समाज में न्याय केवल कानूनों से नहीं आता, बल्कि सोच से आता है। जब नीति-निर्माता, प्रशासक और नागरिक स्वयं यह मानने लगते हैं कि कमजोर व्यक्ति की गरिमा और अधिकार सर्वोपरि हैं, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है। अन्यथा लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था बनकर रह जाता है, जिसकी आत्मा धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है।

आज जब विभिन्न देशों में सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और अवसरों की कमी जैसे मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं, तब कुमारप्पा की यह छोटी-सी घटना एक बड़ा संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी राष्ट्र की महानता उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक संपन्नता या राजनीतिक प्रभाव में नहीं, बल्कि इस बात में निहित होती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करता है। जिस समाज में गरीब, श्रमिक, किसान, बुजुर्ग, महिलाएं और वंचित वर्ग सम्मान और सुरक्षा महसूस करते हैं, वही समाज वास्तव में लोकतांत्रिक कहलाने योग्य होता है।

लोकतंत्र की असली पहचान सत्ता के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता में है। यह उस भावना में है जो कहती है कि व्यवस्था का केंद्र सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे कमजोर नागरिक होना चाहिए। जे.सी. कुमारप्पा का जीवन और उनका यह विचार हमें यही सिखाता है कि जब नीतियां, निर्णय और व्यवस्थाएं कमजोर व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तभी लोकतंत्र अपने वास्तविक स्वरूप में जीवित रहता है। यही वह कसौटी है जिस पर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता और सार्थकता को परखा जाना चाहिए।

तृण तृण बिखरती तृणमूल

जब 4 मई 2026 को बंगाल जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार की विदाई का जनादेश सुनाया तब किसी ने भी सपने नहीं सोचा था कि इस हार के बाद तृणमूल कांग्रेस तृण तृण होकर बिखरने लगेगी। बंगाल विधानसभा में तृणमूल के 80 विधायक जीतकर आए थे जिनमें से पहले 58 विधायक अलग हुए फिर उनकी संख्या बढ़कर 64 हो गई, नेता प्रतिपक्ष भी उन्होंने अपने मन का बना लिया। लोकसभा में 19 सांसदों ने बागी होकर अलग गुट बना लिया है, बागियों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है। राज्यसभा सांसदों के त्यागपत्र भी आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुखेदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव तथा प्रकाश चिक बराईक इस्तीफा दे चुके हैं। आश्चर्यजनक रूप से ममता के सबसे करीबी कल्याण बनर्जी भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जिला और पंचायत स्तर पर भी पार्टी की यही स्थिति है। मात्र एक महीना पहले तक यही सांसद और विधायक ममता दीदी के साथ साए की तरह लगे रहते थे। जैसे ही बंगाल की जनता ने सत्ता बदली इन नेताओं का रुख बदल गया। आज ये नेता जिन विषयों पर ममता और अभिषेक बनर्जी को कोस रहे हैं सत्ता में रहते हुए कभी उन विषयों पर मुंह नहीं खोला, आर.जी. कर और संदेशखाली तक ये लोग मुंह में दही जमाए थे। राजनैतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई न कोई केस चल रहा है और सत्ता जाने के बाद ममता दीदी में इनको बचाने का सारथ्य नहीं रहे तो ये भविष्य में किसी जांच और सजा से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तृणमूल सांसदों व विधायकों की लगातार बगावत से यह संकेत भी जा रहा है कि क्या ममता दीदी का अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रति अधिक झुकाव उनकी पार्टी की इस हालत का कारण है। इससे तृणमूल के बागी नेताओं के स्वार्थी चरित्र की भी पोल खुल रही है। दल में तानाशाही इनको तब दिखाई दी जब सत्ता की मलाई छीन गई, यदि अभिषेक बनर्जी की अगुआई में पार्टी जीत गई होती और इनका लूट खसोट का धंधा चलता रहता तो इनकी आज जागी हुई आत्मा सोई पड़ी रहती।

आज जो सांसद बगावती तेवर अपना रहे हैं उनमें से दस पहली बार चुनकर आए हैं। ये तृणमूल नेताओं की वो पीढ़ी है जिसे ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नया चेहरा बनाकर आगे बढ़ाया था। अब यही लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए ममता दीदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं बंगाल में सत्ता में आई पार्टियाँ कम से कम डेढ़-दो दशक सता में रहती हैं, इस तरह आने वाले 15-20 वर्षों तक इनका कोई भविष्य नहीं होगा।

तृणमूल नेताओं के प्रति जनता के गुस्से का आलम ये है कि चुनाव में पार्टी को धूल चटाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा है। आए दिन तृणमूल नेताओं की सड़कों पिटाई की जा रही है। तृणमूल नेता जहां भी जाते हैं जनता उन्हें चोर-चोर कहकर पुकारती है और उन पर टमाटर-अंडे फेंकती है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओ तक पर अंडे टमाटर फेंके जा चुके हैं और पिटाई हो चुकी है। यह भी संभव कि बंगाल की जनता में व्याप्त इस भयंकर आक्रोश से बचने के लिए भी तृणमूल नेता बगावती हो रहे हों।

तृणमूल के जिला स्तरीय नामचीन नेता इस्तीफा दे रहे हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, चंदन नगर के मेयर राम चक्रवर्ती, बिधान नगर के मेयर कृष्णा चक्रवर्ती और कटवा म्युनिसिपलिटी चेयरमैन कमलकांता चक्रवर्ती ने सौ से अधिक पार्षदों सहित इस्तीफा दे दिया है। राज्यभर से तृणमूल से लगातार इस्तीफों व बगावत के समाचार आ रहे हैं। हुगली, नादिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर व दक्षिण -24 परगना जैसे गढ़ों में प्रतिदिन पंचायत सदस्यों के पाला बदलने की ख़बरें आ रही हैं। टीएमसी में बगावत व इस्तीफों के बाद कोलकाता नगर निगम ही भंग कर दिया गया है।

बंगाल में यह भी दावा किया जा रहा है कि इनमें से बहुत से लोग जेल जाने से बचने के लिए यह तरीका अपना रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल का कुख्यात चेहरा और चुनावों के दौरान अपने आप को पुष्पा कहने वाला फाल्टा विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार जहाँगीर खां के जेल जाने से अफरा तफरी का माहौल है। तृणमूल नेताओं के पाप जैसे उतरा रहे हैं। बंगाल पुलिस को संदेशखाली के तालाब से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, एक खेत से करोड़ों का कैश और हथियार मिले हैं। बमों व अन्य हथियारों की फैक्ट्रियां मिल रही हैं। हजारों की संख्या में सफ़ेद साड़ियाँ मिली हैं जो तृणमूल ने चार मई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की विधवाओं को देने के लिए रखी थीं यदि गलती से भी तृणमूल जीत जाती तो यही लोग जो आज इस्तीफा देकर भाग रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के नर संहार का नेतृत्व करते।

अपराधों की जो फेहरिस्त है उसे देखकर लगता है कि ममता दीदी और उनके चाटुकारों का शेष जीवन अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने या फिर जेल में ही बीतने वाला है। एक समय वाराणसी लोकसभा से पीएम नरेंद्र मोदी को हराने और दिल्ली आकर इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली ममता दीदी के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा कर रखना भी मुश्किल हो चुका है।

अभियान

जब ग्रहों की छाया से घिर जाए जीवन: राहु-केतु शांति के लिए भारत के अद्भुत आध्यात्मिक तीर्थ

भारतीय संस्कृति में ग्रहों और नक्षत्रों का महत्व हजारों वर्षों से स्वीकार किया जाता रहा है। वेदों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में मानव जीवन और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंधों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं ग्रहों में राहु और केतु का स्थान अत्यंत रहस्यमयी माना गया है। यद्यपि खगोल विज्ञान के अनुसार ये भौतिक ग्रह नहीं हैं, फिर भी वैदिक ज्योतिष में इन्हें नवग्रहों में शामिल किया गया है और इनके प्रभाव को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण से जुड़े बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन, अप्रत्याशित घटनाएं, भ्रम, मानसिक तनाव, संघर्ष, सफलता, प्रसिद्धि और आध्यात्मिक जागरण जैसे अनुभवों को प्रभावित करते हैं।

कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु या केतु प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के मानसिक तनाव, अस्थिरता, भय, निर्णय लेने में कठिनाई, आर्थिक समस्याओं या पारिवारिक विवादों का सामना करता है। वहीं दूसरी ओर, जब ये ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में राहु और केतु की शांति के लिए विशेष पूजा, जप, दान और तीर्थयात्रा का महत्व बताया गया है। देश के विभिन्न भागों में ऐसे कई मंदिर स्थित हैं जिन्हें राहु और केतु से संबंधित विशेष शक्तिपीठ माना जाता है। इन मंदिरों में श्रद्धालु अपने ग्रह दोषों की शांति और जीवन की समस्याओं से राहत पाने की कामना लेकर पहुंचते हैं। इन पवित्र स्थलों की यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाती है। हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार इन मंदिरों में की गई पूजा व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर राहु-केतु दोष निवारण के लिए सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां उन्हें कालहस्तीश्वर के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल यह मंदिर अपने आध्यात्मिक महत्व के कारण लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। धार्मिक मान्यता है कि यहां विशेष रूप से राहु-केतु पूजा करने से कालसर्प दोष, नाग दोष तथा अन्य ग्रह संबंधी बाधाओं में राहत मिलती है। मंदिर का वातावरण भक्तों को गहन आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। प्राचीन पत्थरों से निर्मित इसकी भव्य संरचना भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है।

तमिलनाडु का तिरुनागेश्वरम नागनाथर मंदिर भी राहु ग्रह से संबंधित विशेष आस्था का केंद्र है। यह मंदिर कुंभकोणम के निकट स्थित है और नवग्रह मंदिरों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां भगवान शिव नागनाथर के रूप में विराजमान हैं। मंदिर में होने वाला विशेष राहु अभिषेक दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मान्यता है कि इस अभिषेक में भाग लेने से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। मंदिर परिसर का शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा श्रद्धालुओं को विशेष अनुभूति प्रदान करती है।

केतु ग्रह की शांति के लिए तमिलनाडु के कीझापेरुमपल्लम में स्थित श्री नागनाथस्वामी मंदिर का विशेष महत्व है। यह मंदिर अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद अत्यंत प्रभावशाली धार्मिक स्थल माना जाता है। यहां आने वाले भक्त केतु दोष निवारण के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करवाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि केतु व्यक्ति को आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला ग्रह है। इसलिए इस मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति के भीतर मानसिक संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। कई श्रद्धालु यहां ध्यान और साधना के लिए भी आते हैं, जिससे उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तेलंगाना का प्रसिद्ध राहु-केतु मंदिर भी देशभर के श्रद्धालुओं के बीच विशेष पहचान रखता है। यह मंदिर अपने शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यहां नियमित रूप से राहु-केतु शांति पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं। मंदिर में आने वाले लोग मानते हैं कि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न मानसिक तनाव और जीवन की बाधाओं को कम करने में यह पूजा सहायक होती है। मंदिर का वातावरण व्यक्ति को सांसारिक चिंताओं से दूर कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है।

चेन्नई के निकट स्थित श्री नीलकंडेश्वर मंदिर भी राहु-केतु पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के साथ-साथ केतु ग्रह की विशेष पूजा की जाती है। यह मंदिर अपने धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक वातावरण के कारण श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है। मान्यता है कि यहां नियमित दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं तथा मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राहु मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर तक पहुंचना स्वयं में एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव देता है। यहां आने वाले श्रद्धालु राहु ग्रह से जुड़े दोषों की शांति के लिए पूजा-अर्चना करते हैं और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर्वतों की शांत वादियां, स्वच्छ वातावरण और धार्मिक ऊर्जा व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को केवल अशुभ ग्रह नहीं माना गया है। वास्तव में ये दोनों ग्रह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण सीख देने वाले माने जाते हैं। राहु जहां महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और भौतिक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं केतु वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि जीवन की कठिन परिस्थितियां व्यक्ति को अधिक मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। राहु और केतु से जुड़ी चुनौतियां भी व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहां ग्रहों की पूजा केवल भय के कारण नहीं की जाती, बल्कि उन्हें ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूप में सम्मान दिया जाता है। मंदिरों में जाकर पूजा करना व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। जब मनुष्य ईश्वर और आध्यात्मिकता से जुड़ता है, तब उसे अपने जीवन की समस्याओं को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। यही कारण है कि लाखों लोग राहु-केतु से जुड़े इन मंदिरों में जाकर केवल ग्रह दोषों की शांति ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति की भी कामना करते हैं।

आज के आधुनिक युग में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है, वहां आध्यात्मिकता का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। लोग सफलता की दौड़ में मानसिक शांति खोते जा रहे हैं। ऐसे समय में धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल व्यक्ति को अपने भीतर लौटने का अवसर प्रदान करते हैं। राहु-केतु से जुड़े ये मंदिर श्रद्धालुओं को यह संदेश देते हैं कि जीवन की हर चुनौती का समाधान केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और ईश्वर में विश्वास में भी निहित है।

इन पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें यहां आकर मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। चाहे इसे धार्मिक आस्था कहा जाए या आध्यात्मिक प्रभाव, लेकिन यह सत्य है कि श्रद्धा मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखने की शक्ति देती है। यही कारण है कि सदियों से ये मंदिर लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

'विकसित पोरबंदर : फर्नीचर पार्क समिट' संपन्न : देश के सबसे अत्याधुनिक फर्नीचर पार्क के लिए पोरबंदर का चयन, 100 हेक्टेयर में आकार लेगा फर्नीचर पार्क

- पोरबंदर के सांसद और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने समिट की अध्यक्षता की : वन, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया भी रहे मौजूद
- गुजरात इंडस्ट्रीज फ्रेंडली राज्य, पोरबंदर के फर्नीचर पार्क से गुजरात का वैश्विक व्यापार बढ़ेगा : केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लॉन्च होने वाली नई औद्योगिक नीति का लाभ पोरबंदर के प्रस्तावित फर्नीचर पार्क के उद्योगकारों को भी मिलेगा : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया
- भारत का फर्नीचर उद्योग ब्रिटेन के बाजारों तक पहुंचने की उम्मीद है : ब्रिटिश उपउच्चायुक्त श्री स्टीव हिकलिंग
- केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने फर्नीचर पार्क की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए देश के अग्रणी उद्योगकारों के साथ संवाद कर उनके सुझाव प्राप्त किए
- समिट में फर्नीचर उद्योग के अग्रणी उद्योगकार शामिल हुए
- उद्योगकार 14 जून को प्रस्तावित फर्नीचर पार्क साइट का दौरा करेंगे
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की नीतियों और प्रोत्साहन के तहत गुजरात में बनेंगे नए इंडस्ट्रियल पार्क, सौराष्ट्र के तटीय इलाकों का होगा विकास

गांधीनगर : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में शनिवार को पोरबंदर में आयोजित 'विकसित पोरबंदर फर्नीचर पार्क समिट' सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस समिट में देशभर के फर्नीचर उद्योग से जुड़े उद्योगकारों ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रोत्साहक नीतियों की जानकारी हासिल की। उद्योगकारों ने प्रतिक्रिया में कहा कि तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण पोरबंदर में वैश्विक व्यापार कनेक्टिविटी की अपार संभावना हैं। साथ ही, यहां उद्योगकारों को मिलने वाली सुविधाएं व्यापार अनुकूल होंगी।

पोरबंदर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस मौके पर उद्योगकारों, निर्यातकों और पोरबंदर के स्थानीय कारोबारियों के साथ-साथ वैश्विक व्यापार से जुड़ी भारत की अग्रणी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह फर्नीचर पार्क प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित पोरबंदर-विकसित गुजरात' से विकसित भारत के संकल्प में अहम भूमिका निभाएगा और पोरबंदर-सौराष्ट्र की वैश्विक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

पोरबंदर के निकट फर्नीचर पार्क के लिए प्रस्तावित साइट तय कर ली गई है। यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में गुजरात सरकार और भारत सरकार के समन्वय से साकार होगा। इसके लिए 100 हेक्टेयर जमीन का चयन भी हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। पोरबंदर के कुछड़ी गांव के पास शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया। उद्योगकार 14 जून को भारवाड़ा कुछड़ी सहित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत आज एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और एक विशाल बाजार के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित हो रहा है, जहां लोगों की क्रय शक्ति लगातार बढ़ रही है। देश में स्थिर और मजबूत सरकार के निर्णायक कदमों एवं स्पष्ट रोडमैप के साथ भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए गए हैं।

श्री मांडविया ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिक प्रगति को अनिवार्य करार देते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबों और किसानों के कल्याण के साथ-साथ उद्योगों के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करने वाली सरकार है, क्योंकि बिना उद्योगों का विकास किए 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना साकार करना असंभव है। उन्होंने पोरबंदर को एक आदर्श स्थान बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के 'बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण' के विजन को पूरा करने की क्षमता रखता है।

केंद्रीय मंत्री ने फर्नीचर पार्क के विचार को समझाते हुए कहा कि यहां डिजाइनिंग, स्किलिंग सेंटर और सभी जरूरी सुविधाएं एक छत तले उपलब्ध होंगी। उन्होंने सभी सहभागियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए यह भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सुझावों पर विचार करके सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सहयोग देने को कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि गुजरात के लंबे समुद्र तट और रणनीतिक भौगोलिक स्थान का लाभ उठाकर राज्य को वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का एक नया पावरहाउस बनाने के लिए कृतसंकल्प है। इसके तहत गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से पोबंदर को एक मॉडल पोर्ट-आधारित औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने का मेगा विजन तैयार किया गया है। साथ ही, पोरबंदर में एक अत्याधुनिक शिप बिल्डिंग क्लस्टर और फर्नीचर पार्क की स्थापना की कवायद शुरू की गई है। गुजरात के वन, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि फर्नीचर पार्क का विचार केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की दीर्घदृष्टि का परिणाम है। पोरबंदर 16वीं सदी से समुद्री व्यापार के जरिए अफ्रीका और खाड़ी देशों से जुड़ा है।

श्री मोढवाडिया ने पोरबंदर को निवेशकों के लिए श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि वापी-अहमदाबाद के गोल्डन कॉरिडोर की तुलना में यहां जमीन की कीमत काफी कम है। यहां सस्ती जमीन और सस्ता श्रमबल उपलब्ध है। पवन और सौर ऊर्जा का हब होने के कारण यहां उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली भी मिलेगी। साथ ही, रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी यह शहर बेहतर है।

श्री मोढवाडिया ने सरकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार और गुजरात सरकार संयुक्त भागीदार हैं। राज्य सरकार जल्द ही देश की सबसे आकर्षक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और डेटा सेंटर पॉलिसी घोषित करने जा रही है, जबकि शिप बिल्डिंग नीति को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति सर्वांगीण विकास और रोजगार को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज फ्रेंडली रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए कलेक्टर कार्यालय से लेकर गांधीनगर तक, सभी स्तर पर तेज गति से मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि दक्षिण कोरिया के सहयोग से पोरबंदर वैश्विक स्तर पर विकास की लंबी छलांग लगाएगा।

ब्रिटिश उपउच्चायुक्त श्री स्टीव हिकलिंग ने पोरबंदर को 'ग्लोबल फर्नीचर हब' के रूप में विकसित करने के प्रोजेक्ट को अद्भुत करार देते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने पोरबंदर के परंपरागत और आधुनिक उद्योगों के समन्वय की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि यहां का फर्नीचर उद्योग ब्रिटेन के बाजारों तक पहुंचेगा। श्री हिकलिंग ने कहा कि गुजरात भारत के आर्थिक विकास का मुख्य इंजन है और देश के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 30 फीसदी है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के उपाध्यक्ष और सीईओ डॉ. अजय कुमार ने कुछड़ी में प्रस्तावित शिप बिल्डिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने चर्चा में बताया कि क्यों पोरबंदर फर्नीचर पार्क के लिए सबसे श्रेष्ठ विकल्प है।

पोरबंदर जिला कलेक्टर श्री एस.डी. धानाणी ने स्वागत भाषण दिया। समिट के अंतर में पोरबंदर और सौराष्ट्र की संस्कृति को उजागर करने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। समिट में पोरबंदर के महापौर श्री सागर मोदी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बाबूभाई बोखीरिया सहित देश के 50 से अधिक फर्नीचर क्षेत्र से जुड़े उद्योगकार तथा विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

फोस्टा चुनाव 2026 सर्वसम्मति का उदाहरण बना : सभी श्रेणियों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, मतदान की नहीं पड़ी जरूरत

सूरत। दक्षिण गुजरात के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक संगठनों में शामिल फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) के वर्ष 2026 के चुनाव इस बार पूरी तरह सहमति, सामंजस्य और संगठनात्मक एकता के माहौल में संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचते-पहुंचते ऐसी स्थिति बनी कि किसी भी श्रेणी में मतदान कराने की आवश्यकता ही नहीं रही। सभी श्रेणियों में उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध पदों के बराबर रहने के कारण सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही फोस्टा चुनाव 2026 ने संगठनात्मक लोकतंत्र के साथ-साथ आपसी सहमति और समन्वय का भी एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है।

फोस्टा लंबे समय से सूरत के व्यापार और विशेष रूप से टेक्सटाइल उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख संगठन रहा है। सूरत का कपड़ा उद्योग देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान रखता है। ऐसे में फोस्टा के चुनावों को हर वर्ष व्यापारिक समुदाय बड़ी गंभीरता और रुचि के साथ देखता है। संगठन की नीतियां, निर्णय और नेतृत्व कपड़ा उद्योग से जुड़े हजारों व्यापारियों और उद्यमियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि फोस्टा के चुनावों को सूरत के व्यापारिक जगत की महत्वपूर्ण गतिविधियों में गिना जाता है।

चुनाव अधिकारियों अशोक जैन, बृजमोहन अग्रवाल और सचिन अग्रवाल के मार्गदर्शन में पूरी चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न की गई। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में नामांकन दाखिल किए गए थे और उसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी की गई। अंतिम दिन तक सभी की निगाहें विशेष रूप से गोल्ड कैटेगरी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि इसी श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक थी और मतदान की संभावना बनी हुई थी।

गोल्ड कैटेगरी में कुल आठ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जबकि उपलब्ध पदों की संख्या सात थी। इस कारण यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यदि सभी उम्मीदवार मैदान में बने रहते हैं तो मतदान कराया जाएगा। हालांकि नाम वापसी के अंतिम दिन अनुप जालान ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उनके नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या सात रह गई, जो उपलब्ध पदों के बराबर थी। चुनाव नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में मतदान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

इस निर्णय के बाद गोल्ड कैटेगरी के सभी सात उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। इनमें महेंद्रसिंह रतनसिंह भायल, तरूणकुमार भगवतीप्रसाद अग्रवाल, मोहनसिंह सरदारसिंह पुरोहित, नवलकिशोर किशनलाल सोनी, अश्विन लीलाधर ठक्कर, भूपेन्द्र डूंगरमल बागरेचा तथा मुकेश खेमचंद केलवानी शामिल हैं। इन सभी को अब संगठन के संचालन और व्यापारिक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

गोल्ड कैटेगरी के साथ ही प्लेटिनम और डायमंड कैटेगरी में भी पहले ही निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बन चुकी थी। प्लेटिनम कैटेगरी में कुल 21 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। इनमें पुरुषोत्तम सत्यनारायण अग्रवाल, गिरीशकुमार जगदीशकुमार मित्तल, अरविंद भरतकुमार गाडिया, नीरज श्रीकिशन अग्रवाल, हंसराज मूलचंद जैन, नानालाल शंकरलालजी राठौड़, सुरेश सागरमलजी मोदी, रामलाल हुकमलाल चौधरी, ओम प्रकाश हस्तीमल गांधी, मनोज मनफुलसिंह अग्रवाल, पंकजकुमार नंदलाल गाडिया, आशीष अशोक मल्होत्रा, राजेश रामनिवास कोठारी, जिग्नेश बटुकभाई भिखड़िया, हरेश देवीदास लखानी, अरविंदकुमार सोहनलाल जैन, सुनील कुमार बाहेती, गुलाबराय तोलाराम शेवानी, हरबंसलाल अरोड़ा, तिलोकचंद हरचंदराय थदानी तथा दिनेश पोपटलाल कटारिया शामिल हैं।

इसी प्रकार डायमंड कैटेगरी में कुल 13 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इनमें अरुणकुमार पाटोदिया, कैलाशकुमार संपतराज वडेरा, शिवराज कालूराम पारीक, दीपचंद हिंदूरामजी चौधरी, गुलशनकुमार लाजपतराय नंदवानी, दिनेश चुन्नीलाल भोगर, रजत माहेश्वरी, श्यामलाल किशनलाल माली, विवेक मुरलीलाल नारनोलिया, सुनीलकुमार मालीराम गोयल, अक्षय मांगीलाल ओसवाल, हरेश सवजीभाई पटेल तथा गौतम रिकबचंद गुलेछा शामिल हैं। इस प्रकार तीनों श्रेणियों में कुल 41 निदेशक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, विरोध या तनाव की स्थिति सामने नहीं आई, जिसे संगठन के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। व्यापारिक समुदाय के कई वरिष्ठ सदस्यों का मानना है कि निर्विरोध निर्वाचन यह दर्शाता है कि संगठन के भीतर आपसी संवाद और समन्वय की मजबूत परंपरा कायम है। फोस्टा से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान समय में टेक्सटाइल उद्योग कई चुनौतियों और अवसरों के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, निर्यात की संभावनाएं, नई तकनीकों का उपयोग और बदलते कारोबारी वातावरण जैसे मुद्दों पर संगठन की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे समय में निर्विरोध चुनी गई नई टीम से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं।

चुनाव समिति ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बताते हुए सभी उम्मीदवारों, सदस्य संस्थाओं तथा व्यापारिक समुदाय का आभार व्यक्त किया है। समिति का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी पक्षों ने परिपक्वता और संगठनात्मक हितों को प्राथमिकता दी, जिसके कारण चुनाव बिना किसी टकराव के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

रेलवे विकास की नई रफ्तार: अहमदाबाद में आधुनिक स्टेशन फाटक मुक्त यातायात और विशाल कोचिंग डिपो की दिशा में बड़े कदम

अहमदाबाद। देश के प्रमुख महानगरों में तेजी से विकसित हो रहे अहमदाबाद को आने वाले वर्षों में रेलवे अधोसंरचना के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। शहर की बढ़ती आबादी, यात्री संख्या और परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर विकास की एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी उद्देश्य से आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में रेलवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, भविष्य की योजनाओं और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह स्पष्ट संकेत मिला कि अहमदाबाद को आधुनिक, सुरक्षित और विश्वस्तरीय रेलवे सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

बैठक में अहमदाबाद के महापौर हितेश बारोट, अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिनेश मकवाना, महानगरपालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष कमलेश पटेल, दरियापुर के विधायक कौशिक जैन तथा अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश सहित रेलवे और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी प्रतिनिधियों ने शहर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे अधोसंरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार, रेलवे फाटकों को समाप्त कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने तथा रेलवे भूमि के बेहतर उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

अहमदाबाद देश के उन शहरों में शामिल है जहां औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही रेलवे यात्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बैठक में विशेष रूप से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रवेश एवं निकास मार्ग, उन्नत सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर पार्किंग सुविधाएं और सुगम आवागमन की दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने जानकारी दी कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया दक्षिणी स्टेशन भवन अगले वर्ष अप्रैल तक यात्रियों के लिए शुरू किए जाने की संभावना है। यह नया भवन स्टेशन के यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह परियोजना शहर की परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी।

बैठक के दौरान रेलवे ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अहमदाबाद में कई स्थानों पर रेलवे फाटक यातायात जाम और दुर्घटनाओं का कारण बनते रहे हैं। केंद्र सरकार के 'फाटक मुक्त भारत' अभियान के तहत इन फाटकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर उनकी जगह आधुनिक ओवरब्रिज और अंडरब्रिज विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मणिनगर क्षेत्र स्थित रेलवे फाटक संख्या-308 पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज परियोजना को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। यह परियोजना पूरी होने के बाद हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी और क्षेत्र में यातायात अधिक सुचारु रूप से संचालित हो सकेगा।

इसके साथ ही ओम नगर रेलवे फाटक पर प्रस्तावित रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य को भी गति देने पर सहमति बनी। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

बैठक में रेलवे भूमि के उपयोग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। महापौर हितेश बारोट ने आंबली रोड स्टेशन के आसपास उपलब्ध रेलवे भूमि के सुनियोजित विकास का प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि इन क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास कर नागरिक सुविधाओं और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी प्रकार विधायक कौशिक जैन ने अहमदाबाद स्टेशन के आसपास की रेलवे भूमि का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे भूमि का बेहतर उपयोग शहर के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

असारवा रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि स्टेशन के चमनपुरा क्षेत्र की ओर दूसरा प्रवेश द्वार विकसित करने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्टेशन तक पहुंचने वाली संपर्क सड़कों और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म विस्तार की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है। यदि प्रस्तावित योजनाएं साकार होती हैं तो असारवा स्टेशन भविष्य में देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्मों वाले स्टेशनों में शामिल हो सकता है। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और ट्रेनों के संचालन में भी अधिक दक्षता आएगी।

बैठक में एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई जिसने रेलवे क्षेत्र में नई संभावनाओं का संकेत दिया। अधिकारियों ने बताया कि वटवा में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा 100 लाइनों वाला कोचिंग डिपो विकसित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल पश्चिम रेलवे बल्कि पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशाल कोचिंग डिपो के निर्माण से ट्रेनों के रखरखाव, निरीक्षण और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

गोरा-घूमा रोड अंडरब्रिज परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को शीघ्र ही जनता के लिए खोलने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से किसानों को मिला आर्थिक सुरक्षा का कवच

- समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद से गुजरात के लाखों किसान बने आत्मनिर्भर
- गत 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर 65,570 करोड़ रुपए मूल्य की 1.05 करोड़ मीट्रिक टन उपज की खरीद हुई

गांधीनगर, : एक दौर था जब किसानों को फसल तैयार होने के बाद बाजार में मिलने वाले कम मूल्य, बिचौलियों के हस्तक्षेप और भुगतान में विलंब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत खरीद व्यवस्था में किए गए सुधारों से गुजरात के लाखों किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम' देने की नीति लागू होने से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम मिलने लगा है। नतीजतन, किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और खेती अधिक लाभकारी बन गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी के मार्गदर्शन में गुजरात ने समर्थन मूल्य पर खरीद की योजना को और भी व्यापक बनाया है। गत एक दशक में हुई खरीद के आंकड़े इसका उत्तम उदाहरण हैं।

मुख्य आंकड़ों पर एक नजर :

- गत 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी : 65,570 करोड़ रुपए
- कुल खरीद की गई उपज : 1.05 करोड़ मीट्रिक टन
- लाभार्थी किसान : 48.98 लाख से अधिक
- मूंगफली खरीद : 31,941 करोड़ रुपए
- कपास खरीद : 17,759 करोड़ रुपए
- वार्षिक लाभार्थी किसान : 2 लाख से बढ़कर 14 लाख
- खरीद मूल्य में बढ़ोतरी : 13 गुना
- एमएसपी में बढ़ोतरी : 54 से 127 फीसदी

मूंगफली और कपास के किसानों को सर्वाधिक फायदा

गुजरात की कृषि अर्थव्यवस्था में मूंगफली और कपास का विशेष महत्व है। गत दस वर्षों में राज्य में 52.48 लाख मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदी के जरिए किसानों को 31,941 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं, कपास की वैश्विक कीमत में गिरावट के दौरान भी सरकार ने 25.23 लाख मीट्रिक टन कपास की खरीद करके किसानों को 17,759 करोड़ रुपए का रक्षा कवच दिया है।

चना और अरहर के किसानों को भी बड़ा लाभ

रबी फसलों का मुख्य आधार माने जाने वाले चने की 16.81 लाख मीट्रिक टन खरीदी की गई और किसानों को 9549 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। जबकि मध्य और दक्षिण गुजरात के किसानों की महत्वपूर्ण फसल अरहर की 4.97 लाख मीट्रिक टन खरीद करके 3222 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

इसके अलावा, सरसो, सोयाबीन, उड़द और मूंग जैसी फसलों की खरीद से भी हजारों छोटे और सीमांत किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।

10 वर्ष में 7 गुना बढ़ोतरी

वर्ष 2016-17 में केवल 2.01 लाख किसानों से 1775 करोड़ रुपए की फसल खरीदी गई थी। आज स्थिति बदल चुकी है। वर्ष 2025-26 के दौरान 14 लाख से अधिक किसानों से 23,800 करोड़ रुपए मूल्य की 32.54 लाख मीट्रिक टन उपज की खरीद की गई है। किसानों की संख्या में 7 गुना और खरीद मूल्य में 13 गुना की बढ़ोतरी इस योजना की सफलता की गवाही देती है।

बुवाई से पहले ही समर्थन मूल्य की घोषणा

केंद्र सरकार अब बुवाई से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की जाती है, ताकि किसानों को फसल बुवाई की कार्ययोजना बनाने में मदद मिल सके। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) बीज, खाद, बिजली, डीजल और मजदूरी जैसे खर्चों का अध्ययन करके समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

सरकार के अनुसार एमएसपी का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है, जिससे किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50 फीसदी मुनाफा मिल सके।

डीबीटी से बढ़ी पारदर्शिता

खरीद प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के उपयोग से किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा होने से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ गई है।

एमएसपी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

गत एक दशक में विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। धान (सामान्य) में 61 फीसदी, गेहूं में 59, बाजरा में 108, ज्वार (हाइब्रिड) में 127 और मूंगफली में 102 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कपास की एमएसपी में भी करीब 99 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

किसानों के अनुसार, समर्थन मूल्य पर खरीद और समय पर भुगतान होने के कारण कृषि क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

पीएम मोदी के 12 साल: स्वामित्व योजना के दूसरे चरण में गुजरात नंबर 1, देश के आधे से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड गुजरात में बने

▸▸ योजना के दूसरे चरण (2021-22) में पूरे देश में बने 32.35 लाख प्रॉपर्टी काड्र्स में से अकेले गुजरात ने रिकॉर्ड 18.50 लाख कार्ड तैयार कर कायम की मिसाल

▸▸ राज्य में 14,900 ड्रोन उड़ानों के जरिए 11,511 गांवों का सटीक मानचित्रण और प्रमाणीकरण पूरा

▸▸ गुजरात में मेहसाणा (1.66 लाख) और अहमदाबाद (1.53 लाख) जिले प्रॉपर्टी कॉर्ड जारी करने में सबसे आगे

▸▸ प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर ग्रामीणों को 50 लाख तक के बैंक ऋण हुए स्वीकृत, ग्रामीण उद्यम को मिली नई रफ्तार

गांधीनगर : पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में जो बड़े कदम उठाए हैं, उनमें 'प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना' एक 'गेमचेंजर' के रूप में सामने आई है। दशकों से गांवों में आवासीय संपत्तियों के सटीक कागजात न होने के कारण ग्रामीण अपने ही घरों के कानूनी अधिकारों और वित्तीय लाभों से वंचित थे।

आज इस योजना के ज़रिए न सिर्फ ग्रामीणों को उनका असली हक मिल रहा है, बल्कि इस महाअभियान में गुजरात ने पूरे देश में 'नंबर 1' बनकर एक नया इतिहास भी रच दिया है। राज्य की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि योजना के दूसरे चरण में देश भर में जितने भी प्रॉपर्टी कार्ड बने हैं, उनमें से आधे से अधिक (50% से ज्यादा) की हिस्सेदारी अकेले गुजरात की रही है।

14,900 ड्रोन उड़ानें और 18.50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड, गुजरात ने 'स्वामित्व योजना' में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कुशल नेतृत्व में गुजरात ने 'प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना' को अभूतपूर्व गति देते हुए पूरे देश के सामने एक 'रोल मॉडल' पेश किया है। अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से ग्रामीण संपत्तियों का सटीक मानचित्रण कर, राज्य सरकार द्वारा अब तक 18.50 लाख से अधिक ग्रामीण संपत्तियों के वैधानिक 'प्रॉपर्टी कार्ड' तैयार किए जा चुके हैं।

वर्ष 2021-22 में इस योजना के दूसरे चरण से जुड़ने वाला गुजरात आज अपने बेहतरीन प्रबंधन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। आँकड़ों पर नज़र डालें तो इस चरण में देश भर के 58,197 गांवों में ड्रोन उड़ानें हुईं और कुल 32,35,260 प्रॉपर्टी कार्ड बने। इनमें से अकेले गुजरात ने 14,900 गांवों में ड्रोन उड़ान और 11,511 गांवों का प्रमाणीकरण कर देश में सर्वाधिक 18,50,614 कार्ड तैयार किए हैं।

मेहसाणा और अहमदाबाद अव्वल, 14,900 ड्रोन उड़ानों से पारदर्शी हुई व्यवस्था

इस महाअभियान को सफल बनाने में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, गुजरात राजस्व विभाग और गुजरात पंचायती राज विभाग का बेहतरीन समन्वय रहा है। ड्रोन सर्वेक्षण और GIS आधारित मैपिंग ने ग्राम नियोजन को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इस प्रक्रिया में ज़िला स्तर पर मेहसाणा (1,66,504 कार्ड) और अहमदाबाद (1,53,125 कार्ड) सबसे आगे हैं। इसके अलावा खेड़ा, बनासकांठा और आणंद में भी 1-1 लाख से अधिक कार्ड तैयार किए गए हैं। पारदर्शी सत्यापन के बाद कार्ड जारी होने से पीढ़ियों से चले आ रहे भूमि विवाद और अदालती मामले लगभग खत्म हो गए हैं।

वित्तीय समावेशन की नई लहर, प्रॉपर्टी कार्ड पर मिल रहा 50 लाख तक के लोन की सुविधा

इस योजना ने ग्रामीण संपत्तियों को एक 'वित्तीय परिसंपत्ति' में बदल दिया है। कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब नागरिक अपने प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग कर बैंकों से आसानी से लोन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात में इस कार्ड के आधार पर 50 लाख तक के बड़े बैंक लोन भी स्वीकृत किए गए हैं।

इससे गांवों में व्यवसाय, शिक्षा और आजीविका के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिसने महिलाओं और वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक 'गेमचेंजर' की भूमिका निभाई है। योजना को जन-जन तक पहुँचाने के लिए राज्यभर में 14,000 से अधिक ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है, जो 'डिजिटल और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत' के विजन को साकार कर रहा है।

भावनगर मंडल पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित,सतर्कता जागरूकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर दिया गया विशेष जोर

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (Capacity Building Training Programme) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता, सत्यनिष्ठा, आचरण नियमों के प्रति समझ विकसित करना तथा कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करना था।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सतर्कता विभाग के विजिलेंस इंस्पेक्टर श्री प्रदीप राउत एवं श्री संतोष साहू ने कर्मचारियों को सतर्कता संबंधी नियमों, प्रक्रियाओं तथा व्यवहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अपने संबोधन में विजिलेंस इंस्पेक्टरों ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपने कार्यों का निष्पादन सदैव निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अनुरूप करें तथा

प्रत्येक स्तर पर सतर्कता एवं पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि नियमों की समुचित जानकारी और उनका प्रभावी अनुपालन न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाइयों एवं असुविधाओं से भी बचाता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक कार्मिक अधिकारी श्री संतोष कुमार वर्मा ने विभिन्न व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सतर्कता के साथ करने का संदेश दिया।

श्री वर्मा ने सुझाव दिया कि मंडल के प्रमुख स्टेशनों एवं कार्यस्थलों पर, जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। इससे कर्मचारियों को नियमों एवं प्रक्रियाओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त होगी तथा वे अपने कार्यों का निष्पादन अधिक दक्षता एवं जवाबदेही के साथ कर सकेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों ने इस उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण के आयोजन के लिए कार्मिक विभाग एवं सतर्कता विभाग की सराहना की तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के नियमित आयोजन की आवश्यकता व्यक्त की।

कार्यक्रम का सफल संचालन मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक श्री शैलेश कुमार द्वारा किया गया।

विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में महेसाणा रेलवे स्टेशन पर रक्तदान शिविर का आयोजन

'विश्व रक्तदान दिवस' के उपलक्ष्य में महेसाणा रेलवे स्टेशन पर आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह सराहनीय पहल महेसाणा रेलवे स्टाफ के 'रेलवे सेवार्थ ग्रुप' द्वारा की गई, जिसमें रेल कर्मियों और उनके परिवारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक,अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन अहमदाबाद की चेयरमैन श्रीमती शेफाली गुप्ता उपस्थित रहीं।

'रेलवे सेवार्थ ग्रुप' के इस पुनीत कार्य में रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों ने पूरे उत्साह के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कुल 101 यूनिट रक्त एकत्रित किया।

DRM श्री वेद प्रकाश ने सभी रक्तदाताओं को इस जीवनदायी योगदान के लिए बधाई दी और रेलवे सेवार्थ ग्रुप के सेवा भाव की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य करते

रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए रक्तदान को मानवता की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम बताया तथा समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति से नियमित रूप से रक्तदान करने का आह्वान किया।

WRWWO की चेयरमैन श्रीमती शेफाली गुप्ता ने कार्यक्रम के बेहतरीन प्रबंधन की जमकर सराहना की। इस दौरान उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुझाव देते हुए कहा कि अहमदाबाद डिवीजन में रेलवे का खुद का एक समर्पित 'ब्लड बैंक' होना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में रेल कर्मचारियों और आमजन की त्वरित मदद की जा सके।

समारोह के दौरान रक्तदाताओं की सराहना करते हुए दो अधिकारियों, सहायक वाणिज्य प्रबंधक-FM और सहायक मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर महेसाणा को उनके उत्कृष्ट सहयोग के लिए मुख्य अतिथियों द्वारा स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे, जिनमें वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर,वरिष्ठ मंडल इलैक्ट्रिक इंजीनियर-टीआरडी,वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर-जी,मंडल इंजीनियर-नॉर्थ एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक-FM उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गिफ्ट सिटी में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के नए डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन किया

▸▸ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज गुजरात को वैश्विक टेक्नोलॉजी हब के तौर पर और मजबूत बनाएगी

▸▸ कंपनी का निवेश उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के नए डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन किया। गिफ्ट सिटी के प्रज्ञा-2 भवन के 7वें और 8वें तल पर शुरू हुआ यह अत्याधुनिक सेंटर गुजरात के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

इस सेंटर के शुरू होने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में नए अवसरों का सृजन होगा, साथ ही उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

बता दें कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज दुनिया की अग्रणी डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, बीमा, विनिर्माण, रिटेल, पर्यटन और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी-आधारित सॉल्यूशन प्रदान करती है। दुनिया के कई देशों में कामकाज का संचालन करने वाली हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में अगले तीन वर्षों में लगभग 1000 उच्च कौशल वाले रोजगार का सृजन करने की क्षमता है।

गिफ्ट सिटी में हेक्सावेयर के डिलीवरी सेंटर की स्थापना गुजरात के टेक्नोलॉजी और नवाचार-आधारित विकास को और मजबूत बनाएगी।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सह कार्यकारी निदेशक श्री आर. श्रीकृष्णा सहित कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) श्री विकास कुमार जैन सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

गुजरात में शराबबंदी के दावों के बीच बेरोकटोक शराब का कारोबार हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात में, जहाँ गुजरात के सपूत महात्मा गांधी ने शराबबंदी की थी, आज शायद ही कोई ऐसा शहर या गाँव बचेगा जहाँ देसी और विदेशी शराब न मिलती हो। फिर भी, हम सबके लिए सुरक्षा का नारा लगाते हुए गुजरात मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं, जो हास्यास्पद है। इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहाँ लोगों की सोचने-समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है, वहाँ शासक विकास के नाम पर उसे लूटते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

गुजरात से आज की ताजा खबर यह है कि गांधीनगर स्थित राज्य निगरानी प्रकोष्ठ की टीम ने नाडियाड-पेटलाड मार्ग पर वैलेटवा के पास नहर के किनारे तीन लोगों के एक गिरोह से 5,07,644 रुपये मूल्य की 1033 बोतलें विदेशी शराब जब्त की हैं। इनमें भाजपा के खेड़ा जिला पंचायत सदस्य सहित दो अन्य शराब तस्कर भी शामिल हैं। टीम ने फरार खेड़ा जिला पंचायत सदस्य प्रफुल उर्फ स्वामी उमेद परमार समेत दो अन्य शराब तस्करों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं।

यह गांधी नगर के गुजरात में हर जगह बिकने वाली शराब के बारे में है। इतनी शराब आ रही है, बिक रही है, पी जा रही है, फिर भी आज तक क्या किसी आईपीएस, एसीपी, डीसीपी, एसपी या पीआई जैसे उच्च अधिकारियों पर कहीं कोई हमला हुआ है? नहीं, क्योंकि ऐसे उच्च अधिकारियों को गांधीनगर और दिल्ली में बैठे अपने गुरुओं से "प्रशासन" की चर्चा करने के बाद गुजरात और खासकर सूरत में पोस्टिंग मिलती है। और फिर कहा जाता है कि ये उच्च अधिकारी, जो अपने गुरुओं को पैसों से भरे बैग देकर आए हैं, जब सेवानिवृत्त होते हैं या कहीं और तबादला हो जाते हैं, तो अपने साथ पैसों से भरे बैग ले जाते हैं। और यही कारण है कि गुजरात में अवैध शराब का धंधा बेकाबू हो गया है। यहां यह बताना जरूरी है कि कुछ ही दिन पहले सूरत में उधना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रोड नंबर 6 पर 21 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता जय दलाल की हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद महिलाओं ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया और छापा मारा। उधना पुलिस स्टेशन के पीआई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्तब्ध रह गए और उन्होंने दो हेड कांस्टेबल, जिग्नेश अंबालाल और आनंद कुमार रत्नाभाई का तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय में तबादला कर दिया और मामला सुलझ गया। तो यहाँ सवाल उठता है कि जब किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की खुलेआम हत्या हो जाती है, तो क्या सिर्फ हेड कांस्टेबलों का तबादला करके संतुष्ट हो जाना उचित है? क्या किसी अन्य अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ कनिष्ठ कर्मचारियों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया, पीएसआई, पीआई या उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं? क्या उनका (हेड कांस्टेबलों का) शराब तस्करों के साथ कोई संबंध था? क्या उनका धंधा उनके संरक्षण में चल रहा था? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूरत समेत राज्य के छोटे-बड़े गांवों में शराब का दानव बेखौफ नाच रहा है और कई परिवारों को निगल रहा है, फिर भी सरकार सिर्फ सुरक्षा का अलार्म बजा रही है। ऐसे समय में, अगर पूरी जिम्मेदारी लेनी है, तो

गृह मंत्री, डीजीपी, हर शहर के पुलिस आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों के डीवाईएसपी की जिम्मेदारी बनती है। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए, तबादला किया जाना चाहिए या कड़ी सजा दी जानी चाहिए, तभी अन्य अधिकारी शराब तस्करों की अनदेखी करेंगे। लेकिन इन सब के बजाय, साधारण हेड कांस्टेबलों या साधारण पीएसआई को बदलने से शराब की बिक्री नहीं रुकेगी और आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार की ओर मुड़कर नहीं देखेंगे।

गुजरात सरकार 15 जून को नई औद्योगिक नीति 2026 का करेगी अनावरण

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल एवं माननीय उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी करेंगे राज्य की नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ

गांधीनगर : गुजरात सरकार 15 जून को अपनी बहुप्रतीक्षित औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण करने जा रही है। इस नई नीति का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की गरिमामय उपस्थिति में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में किया जाएगा।

नई औद्योगिक नीति से राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा भारत के अग्रणी औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य के रूप में गुजरात की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक एवं दूरदर्शी रोडमैप मिलने की अपेक्षा है।

गुजरात की प्रगतिशील औद्योगिक विकास यात्रा और निवेशक-अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, आगामी नीति में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को और बेहतर बनाने, एडवांस्ड मैन्युफ़ैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देने, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने तथा उभरते एवं उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में निवेश को सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है।

वर्षों से गुजरात विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, सक्रिय प्रशासन, मजबूत कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन के बल पर घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा निवेश स्थली के रूप में स्थापित हुआ है।

नई औद्योगिक नीति गुजरात की मौजूदा औद्योगिक शक्तियों को और मजबूत करते हुए राज्य में निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगी। साथ ही, यह नीति गुजरात की आर्थिक प्रगति को तेज करने, निवेशकों के लिए राज्य की आकर्षण क्षमता बढ़ाने तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उसकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अब अखबार में खाना पैक करना अपराध है, एफएसएसएआई ने इसे पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। मुंबई में एक वड़ापाउ विक्रेता ने वड़ापाउ को अखबार में लपेटकर ग्राहक को दे दिया। इस पर बीएमसी और एफएसएसएआई की पश्चिम जोन टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस घटना के बाद ट्रकों, स्टॉलों, क्लाउड किचन, कैटरर्स और हॉकरों को अखबार में खाद्य पदार्थ पैक न करने का आदेश जारी किया गया है। इसके चलते अब से पूरे भारत में अखबार में पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने यह आदेश जारी किया है। इसमें यह प्रावधान भी है कि आदेश का पालन न करने वालों को जेल भी हो सकती है। अखबार में इस्तेमाल होने वाली स्याही अगर खाद्य पदार्थों में मिल जाए तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है, इसीलिए यह आदेश

जारी किया गया है।

ऐसे खाद्य पदार्थ न केवल आपको बीमार

कर सकते हैं बल्कि कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। वड़ा पाव, समोसे, पकौड़े जैसे तैलीय व्यंजन अखबार में लपेटकर परोसे जाते हैं और गर्म होने के कारण अखबार पर लगी स्याही को सोख लेते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अखबारों में इस्तेमाल होने वाली स्याही में सीसा जैसे कई रसायन और धातुएं होती हैं। सीसा कैंसरकारक होता है और अगर इसका सेवन किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के नए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अखबारों में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद अब FSSAI ने भी पूरे भारत में अखबारों में खाद्य पदार्थों को परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सूरत में वाल्मीकि समाज की बैठक हुई नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज की एक बैठक 13 जून, 2026 को सूरत मुखम में प्रदेश अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें सूरत शहर के सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल डी. मेवाड़ा उपस्थित थे, जिन्होंने समाज से कठिनाइयों का सामना करने और बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज को किसी भी कठिनाई से नहीं डरना चाहिए और रीति-रिवाजों और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने का आग्रह किया। कांतिभाई सोलंकी ने सभी से समाज की प्रगति के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। अश्विनभाई वैष्णव और शशिकांत सोलंकी भी उपस्थित थे। भाई लाल वैष्णव ने मुख्य मंच से कहा कि समाज को केवल नौकरियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि लघु एवं लघु उद्योग भी स्थापित करने चाहिए। बैठक में उपस्थित वडोदरा शहर के कार्यकर्ताओं ने भी समाज के लाभों और रीति-रिवाजों पर चर्चा की।

वडोदरा स्थित गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को निर्वाचित किया गया है। उपाध्यक्षः- हरीशभाई छगनभाई संपत, उपाध्यक्षः- मनहरभाई लल्लूभाई सोलंकी, उपाध्यक्षः- विनोदभाई रमनभाई सोलंकी, महासचिवः- नरेशभाई धनजीभाई सोलंकी निर्वाचित हुए हैं।